ठोस लोक नीति के 10 सिद्धांत

1

सरकारी आर्थिक सहायता संबंधी सिद्धांत: सरकार को जनता (व्यक्तियों और संगठनों) के लिए वही करना चाहिए जो वे खुद अपने लिए नहीं कर सकते.

2

यदि सरकार काम नहीं कर पाती है तो एक ठोस नीति के तहत उसके विरुद्ध भी वही मानक, प्रतिमान और सजा के प्रावधान आरोपित किए जाने चाहिए जो राज्य के नागिरकों पर लागू होते हैं.

3

एक ठोस नीति विकल्पों और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी करती है.

4

एक ठोस नीति के अंतर्गत जनता के सभी समूहों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक परिणामों का विचार किया जाता है, महज नीति के पीछे निहित अच्छे इरादों को नहीं.

5

एक ठोस नीति प्रशासन को सुचारु रूप से चलने देने में मददगार (करों और व्यय संबंधी निर्णयों को लेकर) होगी और यह सरकार को लोगों के करीब ले जाएगी.

6

एक ठोस नीति फ्रायडमेन के “व्यय संबंधी कानून” (लॉ ऑफ स्पेंडिंग) को प्रोत्साहित करती है:

1. अपना धन अपने ऊपर ही खर्च कीजिए
2. आप अपना धन किसी और पर खर्च कीजिए
3. आप किसी और का धन अपने ऊपर खर्च कीजिए
4. किसी और का पैसा किसी और पर खर्च कीजिए

7

एक ठोस नीति लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बजाए भागीदारी आधारित काम पर ज्यादा भरोसा करेगी. (जनमत संग्रह या करों का संग्रहण नागरिकों की पसंद के अनुसार)

8

ज्यादा लोगों के हितों की परवाह करते हुए एक ठोस नीति वैयक्तिक अधिकारों को बलि नहीं चढाएगी.

9

एक ठोस लोक नीति का आधार यह होना चाहिए कि लोग जवाबदेह, लचीले और स्वशासित होंगे और ये कानून के ढांचे दायरे में होंगे जिन्हें रियायतों का सही भाग मिले.

10

एक ठोस नीति की एक अंतिम तिथि तय होगी.